बृहस्पतिवार, 20 अगस्त, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

शुभमन गिल ने मानव सुथार की जमकर प्रशंसा की

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

तीन दिन में 100 करोड़ पार आवारापन 2

Page-05

विजय सरकार का बड़ा ऐलान

विधायकों को ₹1 लाख मासिक भत्ता और ₹25 लाख हेल्थ कवर!

- नई सरकारी कारें, ₹1 लाख मासिक भत्ता और ₹25 लाख तक का हेल्थ कवर देने का ऐलान किया गया है।
- सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने, डेयरी सेक्टर और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की योजनाएं घोषित की हैं।

तमिलनाडु की राजनीति में बुधवार को उस समय चर्चा तेज हो गई, जब मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली सरकार ने विधायकों और आम लोगों से जुड़े कई बड़े ऐलान किए। विधानसभा में सरकार की ओर से विधायकों के लिए नई सरकारी गाड़ियों, मासिक भत्ते और स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों की घोषणा की गई। इसके साथ ही किसानों और राज्य के डेयरी क्षेत्र के लिए भी कई योजनाओं का ऐलान किया गया।सरकार के मुताबिक, विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जनता के बीच लगातार आने-जाने और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों की निगरानी करने में सुविधा देने के उद्देश्य से नई सरकारी गाड़ियों की व्यवस्था की जाएगी। विधायकों के लिए मासिक भत्ते में भी बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत उन्हें हर महीने एक लाख रुपये का भत्ता दिए जाने की बात सामने आई है।इसके अलावा विधायकों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की भी घोषणा की गई है। सरकार ने 25 लाख रुपये तक के हेल्थ कवर का प्रावधान किए जाने की जानकारी दी। सरकार का तर्क है कि जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं और उन्हें क्षेत्र में लंबे समय तक काम करना पड़ता है, इसलिए परिवहन और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाया जाना जरूरी है।विधानसभा में मुख्यमंत्री की ओर से केवल विधायकों से जुड़े ऐलान ही नहीं किए गए। सरकार ने आम जनता, किसानों और डेयरी सेक्टर को लेकर भी कई योजनाओं की घोषणा की। किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पशुपालन से जुड़े लोगों को बेहतर सुविधाएं देने पर जोर दिया गया।डेयरी क्षेत्र के लिए प्रस्तावित योजनाओं को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि दूध उत्पादन और इससे जुड़े कारोबार को बढ़ावा देने से किसानों और ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आय के अवसर मिल सकते हैं। इसके साथ ही राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी वित्तीय प्रावधानों की घोषणा की गई है। हालांकि, विधायकों को नई कार, एक लाख रुपये मासिक भत्ता और 25 लाख रुपये के स्वास्थ्य कवर की घोषणा राजनीतिक बहस का विषय बन सकती है। सरकार इसे जनप्रतिनिधियों के काम को सुगम बनाने वाली सुविधा के तौर पर पेश कर रही है, जबकि विपक्ष और आलोचक सरकारी खर्च और प्राथमिकताओं को लेकर सवाल उठा सकते हैं।विजय के नेतृत्व वाली सरकार के लिए ये घोषणाएं राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। सरकार एक ओर विधायकों की कार्यक्षमता बढ़ाने का दावा कर रही है, तो दूसरी ओर आम जनता, किसानों और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए घोषित योजनाओं के जरिए व्यापक जनसमर्थन हासिल करने की कोशिश करती नजर आ रही है।

अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के कश्मीर दौरे पर

जम्मू-कश्मीर में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के प्रस्तावित दौरे को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राजदूत के जम्मू-कश्मीर दौरे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि वह सर्जियो गोर से मुलाकात और बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि जम्मू-कश्मीर से जुड़े भारत के आंतरिक मामलों की शिकायत वह किसी दूसरे देश के राजदूत से नहीं करेंगे।उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर अमेरिकी राजदूत जम्मू-कश्मीर आते हैं तो उनके साथ केंद्र शासित प्रदेश की मौजूदा स्थिति, यहां के विकास और क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, किसी विदेशी राजनयिक से बातचीत का उद्देश्य जमीनी स्थिति को समझना और आपसी संवाद बढ़ाना हो सकता है, लेकिन भारत के आंतरिक मामलों का समाधान किसी दूसरे देश की राजधानी में तलाशना उचित नहीं है।मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जम्मू-कश्मीर की समस्याओं का समाधान वाशिंगटन में नहीं, बल्कि भारत सरकार और जम्मू-कश्मीर के स्तर पर ही होना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और स्थानीय प्रशासन के बीच संवाद तथा राजनीतिक प्रक्रिया को मजबूत करना ज्यादा महत्वपूर्ण है।सर्जियो गोर के दौरे को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जम्मू-कश्मीर लंबे समय से भारत और पाकिस्तान के बीच संवेदनशील मुद्दा रहा है। ऐसे में किसी बड़े देश के राजदूत का यहां दौरा राजनीतिक और कूटनीतिक नजरिए से खास महत्व रखता है। अमेरिकी राजदूत के दौरे को लेकर राजनीतिक दलों की अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं।

स्वाति मालीवाल का बड़ा हमला

केजरीवाल पर दिल्ली-पंजाब में भ्रष्टाचार का आरोप

बीजेपी सांसद और आम आदमी पार्टी की पूर्व नेता स्वाति मालीवाल ने बुधवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर बड़ा राजनीतिक हमला बोला। मालीवाल ने आरोप लगाया कि केजरीवाल ने पिछले एक दशक के दौरान दिल्ली में भ्रष्टाचार की व्यवस्था को बढ़ावा दिया और अब पंजाब में भी अपनी राजनीतिक गतिविधियों के जरिए उसी मॉडल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।पत्रकारों से बातचीत के दौरान स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में लंबे समय तक जिम्मेदारी संभालने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने जान-बूझकर किसी मंत्रालय का प्रभार अपने पास नहीं रखा। मालीवाल का आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया ताकि सरकार में किसी तरह का विवाद या कथित घोटाला सामने आने पर उसकी जिम्मेदारी संबंधित मंत्रियों पर डाली जा सके।मालीवाल ने केजरीवाल के नेतृत्व और आम आदमी पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि दिल्ली में सरकार चलाने के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए, जिनको लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए जवाबदेही तय करने के बजाय जिम्मेदारियों को दूसरों पर डालने की कोशिश की गई।बीजेपी सांसद ने अपने बयान में पंजाब का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने के बाद अब आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी गतिविधियों को बढ़ा रही है। मालीवाल के मुताबिक, पंजाब में भी पार्टी की कार्यप्रणाली और प्रशासन को लेकर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि, उनके इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया आना बाकी है।स्वाति मालीवाल पहले आम आदमी पार्टी से जुड़ी रही हैं और अरविंद केजरीवाल के करीबी राजनीतिक सहयोगियों में शामिल थीं। बाद में उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच संबंधों में काफी तल्खी आ गई। मालीवाल के आरोपों के बाद दिल्ली की राजनीति में उनके और AAP नेतृत्व के बीच विवाद लगातार चर्चा में रहा है।

पश्चिम बंगाल में दो होटल अग्निकांडों से मचा हड़कंप

कोलकाता और तारापीठ में 18 लोगों की मौत

पश्चिम बंगाल में लगातार दो दिनों के भीतर हुए दो बड़े होटल अग्निकांडों ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। राजधानी कोलकाता और बीरभूम जिले के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल तारापीठ में अलग-अलग होटलों में आग लगने की घटनाओं में कुल 18 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। लगातार हुई इन घटनाओं के बाद प्रशासन और अग्निशमन विभाग में हड़कंप मच गया है।जानकारी के मुताबिक, कोलकाता में एक होटल में अचानक आग लगने के बाद देखते ही देखते धुआं और लपटें पूरे परिसर में फैल गईं। होटल में मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और बचाव अभियान शुरू किया गया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की और होटल में फंसे लोगों को बाहर निकाला।इसी दौरान बीरभूम जिले के तारापीठ में भी एक होटल में आग लगने की घटना सामने आई। धार्मिक स्थल होने के कारण तारापीठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। होटल में आग लगने के बाद वहां भी भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। बचाव दल ने प्रभावित लोगों को बाहर निकालने का अभियान चलाया।दोनों घटनाओं में कई लोगों की जान चली गई। रिपोर्ट के अनुसार, मृतकों की कुल संख्या 18 तक पहुंच गई है। अधिकारियों ने मृतकों की पहचान और आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी है। बताया गया है कि कुछ होटल मेहमान बांग्लादेशी नागरिक भी थे, जो इलाज के सिलसिले में कोलकाता आए हुए थे। हादसों के बाद सबसे बड़ा सवाल होटल की फायर सेफ्टी व्यवस्था को लेकर उठ रहा है। पुलिस और अग्निशमन विभाग यह जांच कर रहे हैं कि संबंधित होटलों में आग से बचाव के लिए जरूरी सुरक्षा इंतजाम मौजूद थे या नहीं। अधिकारियों की नजर इस बात पर भी है कि क्या होटल प्रबंधन ने अग्निशमन नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन किया था।जांच एजेंसियां होटल के फायर एग्जिट, आपातकालीन रास्तों, अग्निशमन उपकरणों और बिजली के कनेक्शन समेत कई पहलुओं की जांच कर रही हैं। यदि जांच में सुरक्षा नियमों की अनदेखी सामने आती है तो होटल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। लगातार दो बड़े अग्निकांडों ने राज्य में होटल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

भोपाल में 'जेन अल्फा' का हल्लाबोल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डेमोंस्ट्रेशन मल्टीपर्पस स्कूल यानी DMS के छात्रों ने अपने स्कूल के प्रस्तावित विलय के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। रीजनल स्कूल के नाम से पहचाने जाने वाले इस संस्थान को केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS में शामिल किए जाने के प्रस्ताव ने छात्रों, अभिभावकों और स्कूल से जुड़े लोगों के बीच नाराजगी पैदा कर दी है। बुधवार को छात्रों ने स्कूल परिसर के बाहर प्रदर्शन करते हुए फैसले को वापस लेने की मांग की।प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जमकर नारेबाजी की और अपने स्कूल को मौजूदा स्वरूप में बनाए रखने की मांग उठाई। बड़ी संख्या में छात्र हाथों में पोस्टर और तख्तियां लेकर विरोध करते नजर आए। छात्रों का कहना है कि स्कूल की अपनी अलग पहचान और शैक्षणिक व्यवस्था है, जिसे किसी दूसरे संगठन में विलय करने से उसकी मौजूदा व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

आजम खान पर ED का शिकंजा

दिल्ली-UP के करीब 10 ठिकानों पर छापेमारी

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ED ने बुधवार को मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं और आय से अधिक संपत्ति के मामले में बड़ी कार्रवाई की। केंद्रीय जांच एजेंसी की अलग-अलग टीमों ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली में करीब 10 ठिकानों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया।जानकारी के मुताबिक, ED की टीमों ने रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में कई परिसरों पर छापेमारी की। अधिकारियों और सूत्रों के अनुसार, तलाशी अभियान का संबंध जौहर विश्वविद्यालय के निर्माण और उससे जुड़े कथित वित्तीय लेनदेन से है। एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि विश्वविद्यालय से जुड़े निर्माण कार्यों और अन्य गतिविधियों में धन का इस्तेमाल किस तरह किया गया।मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय आजम खान की राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियों से लंबे समय से जुड़ा रहा है। विश्वविद्यालय की स्थापना और इसके संचालन को लेकर पहले भी कई विवाद सामने आ चुके हैं। अलग-अलग मामलों में सरकारी जमीन, निर्माण कार्य, वित्तीय लेनदेन और प्रशासनिक प्रक्रियाओं को लेकर जांच होती रही है।ED की कार्रवाई को लेकर जांच एजेंसी की ओर से विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। हालांकि, सूत्रों के मुताबिक, तलाशी के दौरान दस्तावेजों, वित्तीय रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण सामग्री की जांच की जा रही है। एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित तौर पर कहीं धन का गलत इस्तेमाल या नियमों के विपरीत लेनदेन तो नहीं किया गया।इस कार्रवाई के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। आजम खान लंबे समय से विभिन्न कानूनी मामलों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ कई मामलों में पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई पहले भी सामने आती रही है। ऐसे में ED की ताजा छापेमारी उनके लिए एक और बड़ी कानूनी चुनौती मानी जा रही है।

भारत-सिंगापुर रिश्तों को नई ऊंचाई
जयशंकर ने नए उच्चायोग परिसर की रखी आधारशिला

भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने नए भारतीय उच्चायोग परिसर की आधारशिला रखी।जयशंकर ने कहा कि नया चांसरी कॉम्प्लेक्स दोनों देशों के संबंधों के 'नए युग' का प्रतीक बनेगा और सिंगापुर में भारतीय समुदाय को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराएगा।

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर में बुधवार को नए 'चांसरी कॉम्प्लेक्स' (भारतीय उच्चायोग परिसर) की आधारशिला रखी। विदेश मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि यह उच्चायोग दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के एक "नए युग" को प्रदर्शित करेगा। इस अवसर पर वहां सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन भी मौजूद थे। जयशंकर बृहस्पतिवार से होने वाली चौथी भारत-सिंगापुर मंत्रीस्तरीय गोलमेज (आईएसएमआर) बैठक के लिए सिंगापुर में हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन के साथ नए उच्चायोग परिसर की आधारशिला रखने के कार्यक्रम में शामिल हुआ।" जयशंकर ने कहा, "मुझे विश्वास है कि यह परिसर भारत-सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी के नए युग को प्रदर्शित करेगा और भारतीय समुदाय के लिए सेवाओं को और मजबूत करेगा।" सिंगापुर की 2020 की जनगणना के अनुसार, देश की 40.4 लाख की आबादी में भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी नौ प्रतिशत है। सिंगापुर में भारतीय नागरिक समेत करीब 16.4 लाख विदेशी नागरिक भी रहते हैं। भारतीय उच्चायोग के अनुसार, सिंगापुर में रहने वाले भारतीयों में छात्र और वित्तीय सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), निर्माण तथा समुद्री क्षेत्र में काम करने वाले लोग शामिल हैं। सिंगापुर की चार आधिकारिक भाषाओं में से एक तमिल है। अन्य तीन आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, मंदारिन चीनी और मलय हैं। इससे पहले जयशंकर और बालाकृष्णन ने दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने तथा मौजूदा भू-राजनीतिक स्थिति पर भी "विस्तृत चर्चा" की। जयशंकर ने एक अन्य पोस्ट में कहा, "कल होने वाली चौथी भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक के दौरान उनके (सिंगापुर के विदेश मंत्री के) साथ आगे भी बातचीत करने को लेकर आशान्वित हूं।" आईएसएमआर द्विपक्षीय आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा के लिए एक अहम मंच है। आईएसएमआर की पहली बैठक सितंबर 2022 में नयी दिल्ली में हुई थी और इसके बाद अगस्त 2024 में सिंगापुर में दूसरी बैठक हुई। आईएसएमआर की तीसरी बैठक पिछले साल अगस्त में नयी दिल्ली में हुई थी। जयशंकर के अलावा इस गोलमेज बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी शामिल होंगे। भारत और सिंगापुर ने 2015 में अपने संबंधों को विस्तार देते हुए इसे 'व्यापक रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक बढ़ाया था। इसमें व्यापार और निवेश, डिजिटलीकरण, रक्षा एवं सुरक्षा, शिक्षा, कौशल तथा उभरती हुई प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग शामिल है। सिंगापुर, आसियान (दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का संगठन) में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। सिंगापुर भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का प्रमुख स्रोत है और विदेशी वाणिज्यिक ऋणों तथा विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के सबसे बड़े स्रोत में से एक है। वित्त वर्ष 2024-25 में सिंगापुर भारत का छठा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था। इस अवधि में भारत ने सिंगापुर से 2120 करोड़ अमेरिकी डॉलर का आयात किया, जबकि सिंगापुर को भारत का निर्यात 1440 करोड़ अमेरिकी डॉलर रहा। पिछले 10 वर्षों में सिंगापुर का भारत में वार्षिक निवेश 1000 करोड़ से 1500 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बीच रहा है।

नौ महीने बाद परिवार से मिले इमरान खान बहन नूरीन और पत्नी बुशरा ने की मुलाकात

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान से उनकी बहन और पत्नी ने लगभग नौ महीने बाद मुलाकात की। उनके स्वास्थ्य को लेकर बढ़ती चिंताओं के मद्देनजर, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने उनके लिए साप्ताहिक पारिवारिक मुलाकात की अनुमति दी थी। इसके परिणामस्वरूप, मंगलवार को रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल में उनके परिजनों ने उनसे भेंट की। गौरतलब है कि इमरान खान साल 2023 से ही अडियाला जेल में कैद हैं और कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं। वर्तमान में वे अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में 14 वर्ष की सजा काट रहे हैं। इस बीच, उनकी सेहत को लेकर लगातार चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। पाकिस्तानी समाचार पत्र 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान की बहन नूरीन नियाजी ने इस वर्ष पहली बार उनसे भेंट की। जेल सूत्रों के हवाले से दी गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों के बीच यह मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई, जो करीब 15 मिनट तक चली। इस दौरान नूरीन ने इमरान के स्वास्थ्य का हाल जाना और दोनों के बीच अन्य विषयों पर भी बातचीत हुई। साथ ही, नूरीन ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश से भी अवगत कराया, जिसमें इमरान को चिकित्सीय जांच और उपचार के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, इमरान खान की अन्य बहनों (अलीमा खान और उज्मा खान) तथा उनके चचेरे भाई कासिम जमान को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के राजनीतिक नेताओं को भी इस मुलाकात से दूर रखा गया।

बिना लाइसेंस संचालित नूडल्स और मोटी सेवई फैक्ट्री पर छापा
गंदगी के बीच खाद्य सामग्री तैयार होते मिलने पर फैक्ट्री सील

बांग्लादेश ने गंगा जल संधि पर भारत को आंख दिखाने की कोशिश की

भारत के साथ तनाव के बीच बांग्लादेश ने गंगा जल संधि में गारंटी क्लॉज जोड़ने की मांग की है। यह संधि 2026 में खत्म होने वाली है। ऐसे में इसके रिन्यूअल से पहले बांग्लादेश हर मौसम में गंगा नदी में पानी की उपलब्धता बनाए रखना चाहता है। बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदउद्दीन चौधरी अनी ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार अपने लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए भारत के साथ गंगा जल बंटवारा संधि पर फिर से बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने उम्मीद जताई कि संधि का जल्द ही रिन्यू किया जाएगा, लेकिन साथ ही कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार देश के अधिकारों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों का रुख करने को भी तैयार है।ढाका में स्थित बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड इंटरनेशनल अफेयर्स (BILIA) ऑडिटोरियम में "गंगा जल संधि: फिर से बातचीत के मुद्दे" विषय पर आयोजित एक सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "हमें एक संधि पर हस्ताक्षर करने ही होंगे। बिना संधि के, हमारे पास आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। यह हमारा अधिकार है।" उन्होंने आगे कहा, "अगर ऐसा करने के लिए हमें किसी अंतरराष्ट्रीय मंच पर जाने की जरूरत पड़ी, तो हम उसके लिए तैयार हैं।" अनी ने कहा कि नई संधि में 1977 की गंगा जल संधि की तरह ही एक गारंटी क्लॉज शामिल होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि पद्मा बैराज का निर्माण, जो प्रधानमंत्री तारिक रहमान का चुनावी वादा था, अगले साल जनवरी या फरवरी में शुरू होगा। उन्होंने कहा कि मंत्रालय इस परियोजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है क्योंकि इससे 26 जिलों को फायदा होने की उम्मीद है। अनी ने उम्मीद जताई कि भारत बांग्लादेशी लोगों की भावनाओं और अधिकारों को समझेगा और उनका सम्मान करेगा। हाल की राजनयिक बातचीत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "हम अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ताना संबंध चाहते हैं, लेकिन दोस्ती राष्ट्रीय हितों के आपसी सम्मान पर आधारित होनी चाहिए।"

म्यूनिख एयरपोर्ट पर वियतनाम एयरलाइंस के बोइंग 787 विमान की इमरजेंसी लैंडिंग हुई

जर्मनी के म्यूनिख एयरपोर्ट पर 15 अगस्त को बड़ा हादसा टल गया। हनोई जा रही वियतनाम एयरलाइंस के बोइंग 787 विमान की टेकऑफ के कुछ देर बाद ही इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। वियतनाम एयरलाइंस की Boeing 787-9 फ्लाइट VN-34 टेकऑफ के दौरान मुश्किल में फंस गई। दरअसल, विमान की पूंछ रनवे से टकरा गई, जिसके बाद विमान ने करीब 2 घंटे तक म्यूनिख के ऊपर चक्कर लगाए और फिर सुरक्षित एयरपोर्ट लौट आया।घटना के बाद विमान करीब 9,000 फीट की ऊंचाई पर म्यूनिख के ऊपर लगभग 2 घंटे तक उड़ता रहा। इस दौरान विमान ने ईंधन कम करने के लिए हवा में ही फ्यूल गिराया, जिसके बाद वह म्यूनिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट लौट आया। विमान की टेल-स्ट्राइक (पूंछ के हिस्से के टकराने) से उसे नुकसान भी पहुंचा। हनोई जाने वाली फ्लाइट VN-34 ने 15 अगस्त को दोपहर करीब 1:45 बजे (लोकल समय) म्यूनिख से उड़ान भरी थी। वियतनाम के सरकारी मीडिया के अनुसार, प्लेन में 271 यात्री और 16 क्रू मेंबर सवार थे और वे सभी सुरक्षित हैं। इससे पहले, वियतनाम एयरलाइंस ने कहा था कि फ्लाइट एक "तकनीकी खराबी" के कारण वापस लौट आई थी।फ्लाइट के टेकऑफ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जिसमें विमान रनवे पर तेजी से आगे बढ़ता दिखाई देता है। इसी दौरान एक तेज आवाज सुनाई देती है और विमान की पूंछ रनवे से टकराती नजर आती है। इसके बाद विमान ऊपर उठता है और उसके पीछे धूल का बड़ा गुबार उड़ता दिखाई देता है। घटना के बाद म्यूनिख एयरपोर्ट प्रशासन ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी थी कि उसने अपना नॉर्थ रनवे बंद कर दिया है, जिसके कारण हवाई यातायात में कुछ देरी हो सकती है। विमान ने साउथ रनवे से उड़ान भरी थी लेकिन लैंडिंग नॉर्थ रनवे पर की गई, जिसे बाद में सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था।

अमेरिका-दक्षिण कोरिया की सैन्य कवायद से भड़का उत्तर कोरिया किम शासन ने दी 'आत्मरक्षा' की चेतावनी

एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उत्तर कोरिया के साथ दूरियां घटाने की कोशिश में हैं और दक्षिण कोरिया भी प्योंगयांग के साथ रिश्तों को पटरी पर लाना चाहता है, वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया इन प्रयासों को तरजीह देता नहीं दिख रहा। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'उल्ची फ्रीडम शील्ड' (यूएफएस) से बौखलाए उत्तर कोरिया ने इसे सीधे तौर पर उकसावा करार दिया है और अपनी सुरक्षा के लिए 'आत्मरक्षा' के कड़े कदम उठाने की चेतावनी दी है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने सैन्य अभ्यास की अवधि और दायरा कम करने का फैसला किया है।उत्तर कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी केसीएनए (KCNA) के हवाले से योनहाप ने बताया कि प्योंगयांग ने इस संयुक्त अभ्यास को दुश्मन देशों का आक्रामक सैन्य रुख करार दिया है। उत्तर कोरिया ने स्पष्ट किया कि वह अपने खिलाफ पैदा हो रहे किसी भी सैन्य खतरे को पूरी तरह निष्प्रभावी करने के लिए जरूरी रणनीतिक कदम उठाएगा। हालांकि, अपने बयान में उत्तर कोरिया ने अभ्यास घटाने के ट्रंप के आदेश का सीधा जिक्र करने से परहेज किया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया का यह वार्षिक सैन्य अभ्यास सोमवार को शुरू हुआ था, जिसे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 27 अगस्त तक चलना था। हालांकि, ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद इसे इसी शुक्रवार को समाप्त करने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही कई मैदानी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी रद्द या सीमित कर दिया गया है। गौरतलब है कि ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पर लिखा था कि ये संयुक्त अभ्यास बेहद खर्चीले हैं और उत्तर कोरिया को गलत संदेश भेजते हैं। उन्होंने उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन के साथ अपने बेहतर संबंधों की भी दुहाई दी थी। दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून ने संसद में बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि सोल को ट्रंप के सैन्य अभ्यास घटाने के इस फैसले की पूर्व जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट आने से पहले तक अमेरिकी और दक्षिण कोरियाई अधिकारी भी इस अचानक हुए फैसले से पूरी तरह बेखबर थे। इस बीच, दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने अभ्यास में कटौती के बावजूद अपनी संयुक्त रक्षा क्षमता और सैन्य समन्वय बनाए रखने पर जोर दिया है।

संपादक की कलम से

'एक देश, एक चुनाव' यानी लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने का विचार पहली नजर में प्रशासनिक सुविधा, चुनावी खर्च में कमी और बार-बार होने वाली चुनावी प्रक्रिया से राहत का रास्ता दिखाई देता है। लेकिन किसी भी बड़े संवैधानिक बदलाव को केवल सुविधा के चश्मे से नहीं देखा जा सकता। इसके प्रभाव देश के संघीय ढांचे, लोकतांत्रिक जवाबदेही और जनता के राजनीतिक अधिकारों तक जाते हैं।कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इसी बहस को संसदीय प्रणाली के मूल चरित्र से जोड़ते हुए सवाल उठाया है। उनका तर्क है कि भारत की संसदीय व्यवस्था में सरकार का कार्यकाल किसी निश्चित तारीख से नहीं, बल्कि सदन के विश्वास से तय होता है। यदि कोई सरकार बहुमत खो देती है, गठबंधन टूट जाता है या राजनीतिक परिस्थितियां बदल जाती हैं, तो सरकार का गिरना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे में पूरे देश में चुनावों का एक निश्चित चक्र बनाए रखना संवैधानिक रूप से आसान नहीं होगा।यह भी ध्यान देने योग्य है कि भारत में 1952 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव काफी हद तक एक साथ हुए थे। बाद में अलग-अलग राज्यों और केंद्र में सरकारों के कार्यकाल पूरे होने से चुनावी चक्र अलग होता चला गया। इसलिए आज की स्थिति को केवल अव्यवस्था या अनावश्यक चुनावों का परिणाम मानना अधूरा विश्लेषण होगा। यह भारतीय राजनीति में आए बदलावों और संसदीय लोकतंत्र की स्वाभाविक गतिशीलता का परिणाम भी है।निश्चित रूप से बार-बार चुनाव होने से सरकारी मशीनरी पर दबाव पड़ता है, सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ती है और राजनीतिक दलों का समय व संसाधन चुनावी गतिविधियों में खर्च होता है। चुनावी खर्च कम करना और शासन को चुनावी गतिविधियों से होने वाले व्यवधान से बचाना भी जरूरी है। लेकिन इन उद्देश्यों को हासिल करने के लिए ऐसा रास्ता नहीं चुना जाना चाहिए जिससे राज्यों की राजनीतिक स्वायत्तता कमजोर हो।भारत केवल एक प्रशासनिक इकाई नहीं, बल्कि अनेक राज्यों और विविध राजनीतिक परिस्थितियों वाला संघ है। किसी राज्य की जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि वह अपने राज्य की सरकार के प्रदर्शन के आधार पर समय पर अपना फैसला दे सके। यदि किसी राज्य में सरकार बहुमत खो देती है, तो केवल चुनावी कैलेंडर बचाने के लिए उस विधानसभा को लंबे समय तक बनाए रखना लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विपरीत हो सकता है।इसलिए 'एक देश, एक चुनाव' पर बहस 'पक्ष या विपक्ष' के राजनीतिक नारों से आगे बढ़नी चाहिए। चुनावी खर्च और प्रशासनिक व्यवधान कम करने के बेहतर विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। चुनाव सुधारों का उद्देश्य लोकतंत्र को अधिक सुविधाजनक बनाना जरूर हो, लेकिन उससे पहले यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि लोकतंत्र की जवाबदेही, राज्यों की स्वायत्तता और जनता के निर्णय का अधिकार कमजोर न पड़े।आखिरकार, चुनाव लोकतंत्र का बोझ नहीं, उसकी सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया हैं। सुधार ऐसे हों जो चुनावों को कम नहीं, बल्कि लोकतंत्र को अधिक मजबूत बनाएं।

सोनिया गांधी की आत्मकथा में खुलेंगे जिंदगी के अनकहे पन्ने

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आगामी आत्मकथा 'Belonging: A Journey of Love' को लेकर कहा है कि अपने जीवन के निजी अनुभवों और भावनाओं को शब्दों में ढालना उनके लिए आसान नहीं था।544 पन्नों की यह आत्मकथा 10 नवंबर को हार्डकवर, ई-बुक और ऑडियो संस्करण में प्रकाशित होगी, जिसमें इटली में बिताए बचपन से लेकर भारत में उनके राजनीतिक और पारिवारिक जीवन तक का जिक्र है।सोनिया गांधी के मुताबिक, अपनों को खोने का गहरा दर्द ही उन्हें राजनीति की दुनिया में लेकर आया और किताब में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी तथा गांधी परिवार से जुड़े कई भावनात्मक दौर की झलक मिलेगी।

कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी आगामी आत्मकथा के बारे में कहा कि अपने जीवन के बारे में लिखना उनके लिए आसान नहीं था क्योंकि इसके लिए उन्हें वर्षों से अपने दिल में संजोकर रखे गए अनुभवों और भावनाओं को उजागर करना पड़ा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि उनके जीवन में गम का पहाड़ टूटने और अपनों को खोने का दर्द ही उन्हें राजनीति में लेकर आया। सोनिया गांधी की 544 पन्नों की 'Belonging: A Journey of Love' शीर्षक वाली आत्मकथा नवंबर में प्रकाशित होगी। मंगलवार को न्यूयॉर्क में इस आत्मकथा के प्रकाशक अल्फ्रेड ए. नॉफ की ओर से जारी एक बयान में सोनिया गांधी ने कहा, "गम का पहाड़ टूटने और अपनों को खोने के दर्द ने मुझे राजनीति की दुनिया में ला दिया। तब तक मैं अपनी निजता की पूरी तरह रक्षा करती थी।" उन्होंने कहा, "अपने जीवन के बारे में लिखना मेरे लिए आसान नहीं था। इसका मतलब था ऐसी बातों और उन पलों तथा अनुभवों को साझा करना, जिन्हें मैंने हमेशा अपने दिल में संजोकर रखा था।" सोनिया गांधी की इस आत्मकथा को प्रकाशन संस्था नॉफ 10 नवंबर को हार्डकवर और ई-बुक संस्करण में जारी करेगी। इसका ऑडियो संस्करण भी प्रकाशित किया जाएगा। प्रकाशक की ओर से बताया कि पुस्तक की पहली एक लाख प्रतियों की छपाई की घोषणा की गई है। इस प्रकाशन संस्था का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि वह चाहती हैं कि यह पुस्तक उनके जीवन में आयी "खुशियों और गहरी निराशा से भरी उनकी भावनात्मक यात्रा का प्रमाण बने।" उन्होंने कहा, "मेरे परिवार के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन बहुत कम विवरण ऐसे रहे हैं जो उनके फैसलों के पीछे की वास्तविक भावनाओं और वजहों, उनके कार्यों और उनकी बेहद मानवीय कमजोरियों की सच्चाई तक पहुंच पाए हों।" उन्होंने कहा कि यह पुस्तक "कई मायनों में" उनके परिवार की "मानवीयता" को समर्पित है। इस आत्मकथा में सोनिया गांधी के इटली में बिताए बचपन से लेकर भारत में उनके जीवन तक का वर्णन किया गया है। राजीव गांधी से विवाह, देश की प्रधानमंत्री रहीं इंदिरा गांधी की बहू बनना, इन सबका उल्लेख इस आत्मकथा में किया गया है। सोनिया ने कहा कि राजनीति से धीरे-धीरे दूरी बनाने के बाद जब उन्होंने अपने जीवन को पीछे मुड़कर देखा, तो उन्हें एहसास हुआ कि "उनके जीवन के हर पड़ाव को जोड़ने वाली कड़ी प्रेम और निष्ठा रही है।" उन्होंने अपनी इस यात्रा को "इटली के छोटे शहर में अपने बचपन की सरलता से लेकर भारत में बिताए वर्षों की जटिलता" तक की यात्रा बताया। इस आत्मकथा की शुरुआत वर्ष 1965 इंग्लैंड के कैंब्रिज से होती है। यहां 19 साल की छात्रा सोनिया माइनो को राजीव गांधी से पहली ही नजर में प्यार हो गया और बाद में दोनों ने शादी कर ली। इस किताब में इंदिरा गांधी से उनकी पहली मुलाकात, हिंदी सीखने की उनकी कोशिश, साड़ी पहनना और भारतीय व्यंजनों का आनंद लेना तथा गांधी परिवार पर आए दुखों के पहाड़ का भी जिक्र है। राजीव गांधी के छोटे भाई संजय गांधी की विमान हादसे में मौत के बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई। मां की हत्या के बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और इसके सात साल बाद चुनाव प्रचार के दौरान उनकी भी हत्या कर दी गई।

स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए

केजरीवाल ने जानबूझकर किसी भी मंत्रालय का प्रभार अपने पास नहीं रखा

बीजेपी सांसद और पूर्व आम आदमी पार्टी नेता स्वाति मालीवाल ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मालीवाल ने दावा किया कि केजरीवाल ने दिल्ली में करीब 10 साल तक भ्रष्टाचार की दुकान चलाई और अब पंजाब में भ्रष्टाचार का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर दिया है। बीजेपी सांसद मालिवाल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते जानबूझकर किसी भी मंत्रालय का प्रभार अपने पास नहीं रखा, ताकि किसी घोटाले के सामने आने पर संबंधित मंत्री पर इसकी जिम्मेदारी डाली जा सके। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में केजरीवाल दिल्ली में भ्रष्टाचार की दुकान चला रहे थे। चाहे स्कूलों में क्लासरूम निर्माण का मामला हो, शराब घोटाला हो या कई अन्य कथित घोटाले। उन्होंने बेहद चालाकी से काम किया। बता दें कि स्वाती मालीवाल के बयान ऐसे समय आए हैं जब दिल्ली जल बोर्ड (DJB) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अपग्रेडेशन के लिए टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं और हेरफेर का मामला सामने आया है। इस मामले में AAP नेता सत्येंद्र जैन को भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने गिरफ्तार किया है। स्वाती मालीवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा यह मामला सीधे यमुना की सफाई से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि जब तक दिल्ली में पर्याप्त संख्या में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सही तरीके से नहीं बनाए जाते, तब तक यमुना की सफाई संभव नहीं है। स्वाती मालीवाल ने पंजाब को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में AAP की गतिविधियां कमजोर पड़ने के बाद पंजाब में भ्रष्टाचार का बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है। उन्होंने सत्येंद्र जैन पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें पंजाब में पार्टी के लिए कथित तौर पर कलेक्शन एजेंट बताया। मालीवाल ने सवाल उठाया कि दिल्ली के पूर्व विधायक सत्येंद्र जैन को चंडीगढ़ के सेक्टर-39 में बंगला नंबर 926 कैसे और क्यों आवंटित किया गया। उन्होंने दावा किया कि यह बंगला कई मंत्रियों को आवंटित आवासों से भी अधिक आलीशान है। मालीवाल ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी कथित भ्रष्टाचार की कहानी दिल्ली से पंजाब तक पहुंच गई है। उन्होंने दावा किया कि इस पूरी कथित व्यवस्था के लेखक, निर्देशक और निर्माता अरविंद केजरीवाल हैं, जबकि गिरफ्तार किए जा रहे नेता सिर्फ अभिनेता हैं। वहीं, AAP की राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी AAP नेताओं को निशाना बनाने के अपने पुराने तरीके पर लौट आई है।

'एक देश, एक चुनाव' संघीय ढांचे के लिए खतरा, संसदीय प्रणाली को गलत समझने का नतीजा: शशि थरूर

'एक देश, एक चुनाव (ONOE)' का प्रस्ताव संसदीय प्रणाली के कामकाज के तरीके को गलत समझने का नतीजा है। इस प्रस्ताव का मकसद पूरे भारत में राष्ट्रीय और राज्य चुनावों के लिए एक जैसा और एक ही समय का शेड्यूल लागू करना है। साथ ही, यह संविधान बनाने वालों द्वारा तैयार किए गए संघीय ढांचे के अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा करता है। यह कहना है कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर का। थरूर ने इस बारे में द हिंदू में एक लंबा-चौड़ा लेख लिखा है। डॉ. शशि थरूर ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने आर्टिकल को शेयर करते हुए लिखा-द हिंदू में छपे मेरे लेख में 'एक देश, एक चुनाव' (One Nation One Election) के प्रस्ताव का विश्लेषण किया गया है और यह बताया गया है कि संसदीय प्रणाली में यह क्यों काम नहीं कर सकता। थरूर ने लिखा-राष्ट्रीय स्तर पर एकरूपता लाने के नाम पर दर्जनों अलग-अलग राज्यों की राजनीतिक चाल को केंद्र सरकार के साथ एक जैसा करने का मतलब है लोकतांत्रिक मूल्यों के बजाय प्रशासनिक सुविधा को ज्यादा अहमियत देना। केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद डॉ. शशि थरूर ने लिखा-चुनावों को एक साथ कराने का तर्क मुख्य रूप से वित्तीय खर्च के सतही हिसाब-किताब और शासन-प्रशासन के ठप पड़ने की बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई बातों पर आधारित है। फिर भी, यह उस बुनियादी संवैधानिक टकराव को नजरअंदाज करता है जो तब पैदा होता है जब संसदीय लोकतंत्र में राष्ट्रपति-आधारित प्रणाली के तौर-तरीकों को बेढंगे तरीके से थोपा जाता है। थरूर ने लिखा संसदीय शासन प्रणाली का मुख्य सिद्धांत यह है कि कार्यपालिका अपनी वैधता सीधे विधायिका से प्राप्त करती है और उसके प्रति लगातार जवाबदेह रहती है। राष्ट्रपति प्रणाली के विपरीत, जहाँ कार्यपालिका को एक निश्चित और न बदले जा सकने वाले कार्यकाल के लिए स्वतंत्र रूप से चुना जाता है, संसदीय कार्यपालिका पूरी तरह से विधायी बहुमत की इच्छा पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा-प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तभी तक शासन करते हैं जब तक उन्हें सदन का विश्वास प्राप्त होता है। नतीजतन, संसदीय प्रणाली स्वाभाविक रूप से लचीलेपन पर आधारित होती है। कार्यकाल सख्ती से तय नहीं होते क्योंकि गठबंधन सरकार का गिरना, अविश्वास प्रस्ताव का सफल होना, या विधायी समीकरणों में बदलाव स्वाभाविक रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में बदलाव का कारण बनते हैं।

थरूर ने लिखा-यही कारण है कि भारत में चुनाव, जो 1952 से 1967 तक एक ही समय-सारणी पर होते थे, अब वैसे नहीं होते। केंद्र और राज्यों में सरकारें अलग-अलग समय पर गिरीं जब उन्होंने अपना विधायी बहुमत खो दिया और उसके बाद उसी के अनुसार चुनाव हुए, जिससे आज ऐसी स्थिति बन गई है कि हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं।

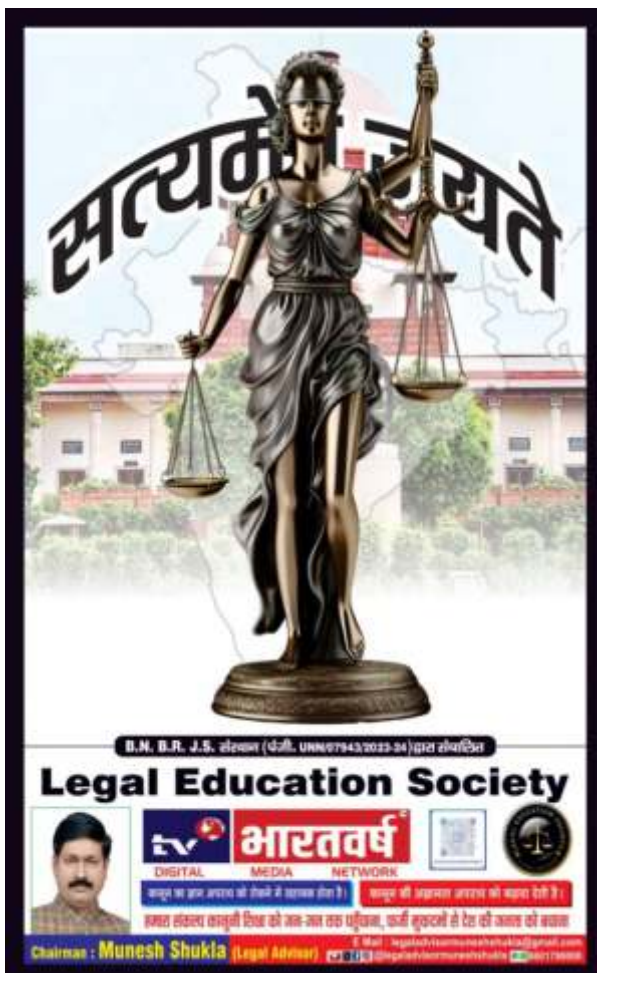

इंजीनियरिंग कॉलेजों में सीटों का संकट
तमिलनाडु के 23 कॉलेजों में एक भी एडमिशन नहीं

हर साल इंजीनियरिंग एडमिशन के लिए लाखों छात्रों की भीड़ होती है लेकिन 2026 में तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। इस बार कई कॉलेजों में सीटें खाली रहे गई हैं। इसके पीछे की वजह भी सामने आई है। इस बार तमिलनाडु में TNEA काउंसलिंग के दूसरे राउंड के बाद 167 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 90 प्रतिशत से अधिक सीटें खाली बच गई हैं जबकि 23 कॉलेजों में एक भी छात्र नहीं पहुंचा है।काउंसलिंग डेटा के एनालिसिस के अनुसार, TNEA 2026 के दूसरे राउंड के बाद 1 लाख से ज्यादा सीटें खाली हैं। अब तक कुल सीटों में से सिर्फ 41% ही भरी हैं। आइए जानते हैं इंजीनियरिंग एडमिशन का यह ट्रेंड क्यों है और इसके बारे में विस्तार से।

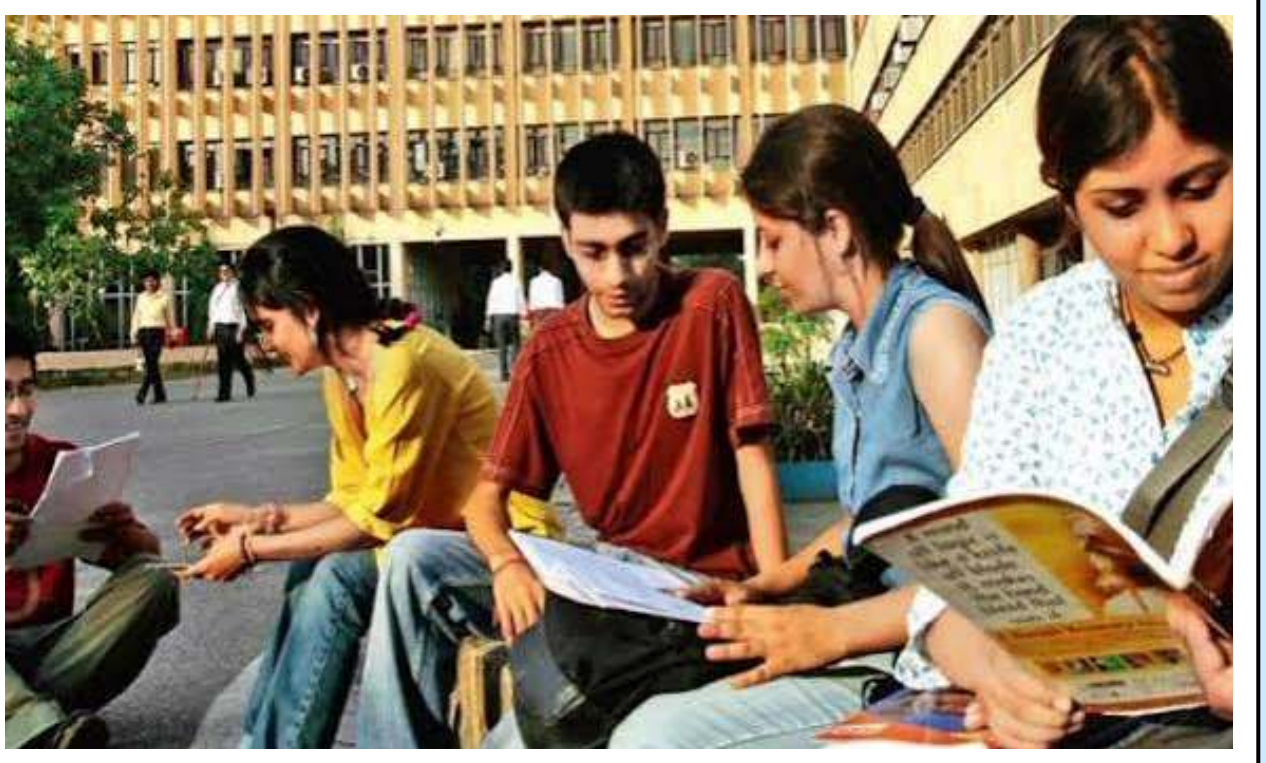

TOI की रिपोर्ट के मुताबिक, तमिलनाडु में कई सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों ने अपनी ज्यादातर सीटें भर ली हैं। हालांकि, 167 इंजीनियरिंग कॉलेजों में 90 प्रतिशत सीटें खाली हैं और 23 कॉलेजों में तो 2 राउंड के बाद भी एक भी एडमिशन नहीं हुआ है। राउंड 2 के आंकड़ों के मुताबिक, बीटेक की ब्रांच कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) में 17,124 एडमिशन हुए।

इसके बाद ECE में 12,000 से ज्यादा और IT में 6,282 एडमिशन हुए हैं।

पिछले साल की तुलना में भरी गई सीटों की संख्या 5,236 कम हो गई है।

अपनी कुल सीटों में से 50% से ज्यादा सीटें भरने वाले कॉलेजों की संख्या भी पिछले साल के 147 से घटकर 111 रह गई।

इंजीनियरिंग एडमिशन के आंकड़ों को देखा जाए तो राज्य में इस साल जनरल काउंसलिंग के दूसरे राउंड में बुलाए गए 93,116 छात्रों में से 43,132 (46%) छात्र काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए हैं। तमिलनाडु इंजीनियरिंग एडमिशन (TNEA) के अधिकारियों ने बताया कि 7.5% स्पेशल रिजर्वेशन और जनरल काउंसलिंग समेत प्रोविजनल अलॉटमेंट की संख्या 59,951 थी। जानकारों का मानना है कि छात्रों के मैनेजमेंट कोटे के तहत अपनी पसंद के कोर्स में दाखिला लेने और इंजीनियरिंग काउंसलिंग से पहले ही डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा एडमिशन पूरा कर लेने की वजह से अनुपस्थिति रही है। इस साल 12वीं के अंकों में गिरावट के कारण कॉलेजों को तीसरे राउंड में ज्यादा एडमिशन की उम्मीद है। इस साल कट-ऑफ मार्क्स 10 तक गिरकर लगभग 150 हो गए हैं। राज्य में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और AI और डेटा साइंस जैसे कोर्स छात्रों की पहली पसंद बने रहे। वहीं कॉलेजों ने बताया कि इस साल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसे कोर्स में एडमिशन में बढ़ोतरी देखी गई।

यूपीएसएससी लोअर पीसीएस भर्ती परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी

यूपीएसएससी लोअर पीसीएस की 2587 वाली भर्ती की परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं। कैंडिडेट्स उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in से अपने हॉल टिकट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। लेकिन प्रवेश पत्र तभी डाउनलोड होगा जब अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करेंगे। बिना फीस भरें आप प्रवेश पत्र चेक नहीं कर सकेंगे। यूपीएसएससी लोअर पीसीएस एडमिट कार्ड से जुड़ा ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। जिसमें जानकारी दी गई है कि परीक्षा देने जा रहे उम्मीदवार 19 अगस्त से अपने हॉल टिकट डिटेल्स भरकर ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वेबसाइट के साथ-साथ इसे ईमेल आईडी पर आए लिंक के जरिए भी प्रवेश पत्र चेक किया जा सकता है।उत्तर प्रदेश सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2026 23 अगस्त को सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित होगी। जिसके लिए एग्जाम सिटी के बाद अब प्रवेश पत्र भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो गए हैं। इसे आप नीचे बताए स्टेप्स के जरिए ऑनलाइन चेक कर सकेंगे- सबसे पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in पर जाएं।

होमपेज पर आपको Main Examination Fee Deposition के लिंक पर क्लिक करें।

अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि, जेंडर, कैटेगिरी सेलेक्ट करके वेरिफिकेशन कोड भरें।

अब नीचे Click Here to Proceed पर जाएं।

फीस भरने के बाद Download Admit Card For the Main Examination के लिंक पर जाएं।

यहां अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और जेंडर भरने के बाद वेरिफिकेशन कोड फिल करके सबमिट करें। आपकी स्क्रीन पर एडमिट कार्ड आ जाएगा। अब आप इसका प्रिंट आउट या पीडीएफ निकाल सकते हैं।

Satwik-Chirag को मिला Walkover
BWF World Championship 2026 में सीधे प्री-क्वार्टर में एंट्री

WTC पॉइंट्स टेबल में भारत का PCT बढ़ा लेकिन रैंकिंग में बदलाव

भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए श्रीलंका को पहले टेस्ट मैच में 165 रनों से हरा दिया है। गॉल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए इस मैच में भारत से मिले 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका की पूरी टीम दूसरी पारी में 206 रन बनाकर ऑलआउट हुई। इसी के साथ भारत ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-1 से बढ़त बना ली है। इस जीत के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में भारत ने अपनी स्थिति में मामूली सुधार किया है। इस डबल्यूटीसी साइकिल में खेले गए 10 टेस्ट मैचों में भारत की यह पांचवीं जीत है। उनका पॉइंट्स प्रतिशत (PCT) 48.14 से थोड़ा बढ़कर 53.33 हो गया है। हालांकि उनकी रैंक में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वे अब भी पांचवे नंबर पर ही हैं। वहीं श्रीलंका पॉइंट्स टेबल में छठे स्थान पर बना हुआ है, लेकिन पांच मैचों में अपनी दूसरी हार के साथ उनका पॉइंट्स प्रतिशत गिरकर 33.33 हो गया है। न्यूज़ीलैंड में दो टेस्ट मैच खेलने से पहले भारत को इस सीरीज़ में एक और टेस्ट खेलना है। उनका यह साइकल अगले साल ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ घरेलू मैदान पर होने वाली पांच मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफ़ी सीरीज़ के साथ पूरा होगा। गॉल टेस्ट के बाद भारत के इस विश्व टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल में अब आठ मुकाबले बाकी हैं। भारत को ये सभी मुकाबले बेहद अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि टीम पहले ही चार मैच गंवा चुकी है। भारत को अगर फाइनल में जगह बनानी है तो बचे हुए कम से कम सात या छह मुक़ाबले जीतने होंगे। ऑस्ट्रेलिया डबल्यूटीसी की अंक तालिका में टॉप पर बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने अबतक खेले गए 9 मैचों में 7 मुक़ाबले जीते हैं। वह 84 अंक और 77.77 पॉइंट्स प्रतिशत के साथ पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर चार मैचों में तीन जीतकर 75 विनिंग प्रतिशत के साथ दक्षिण अफ़्रीका है। न्यूजीलैंड छह मैचों में चार जीतकर 72.22 विनिंग प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। वहीं बांग्लादेश पांच मैचों में तीन जीतकर 66.67 विनिंग प्रतिशत के साथ चौथे नंबर पर है।

टेस्ट रैंकिंग एक बार फिर से बदल गई ट्रेविस हेड टॉप से सीधे तीसरे नंबर पर चले गए

आईसीसी ने अपनी टेस्ट रैंकिंग को फिर से अपडेट कर दिया है। इस बार इसमें जबरदस्त उठापटक नजर आ रही है। ट्रेविस हेड लंबे समय पर नंबर एक बल्लेबाज बने हुए थे, लेकिन अब उनकी बादशाहत खत्म हो गई है। वे अब सीधे नंबर चार पर पहुंच गए हैं। इस बीच इंग्लैंड के हैरी ब्रूक नंबर एक बल्लेबाज बन गए हैं। जो रूट और स्टीव स्मिथ को भी हल्का सा फायदा हुआ है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में अब इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज हैरी ब्रूक नंबर वन बल्लेबाज बन गए हैं। इस बार की रैंकिंग में उन्हें एक स्थान का फायदा हुआ है। उनकी रेटिंग इस वक्त 852 की चल रही है। इंग्लैंड के कप्तान जो रूट को भी एक स्थान का उछाल मिला है। वे अब 840 की रेटिंग के साथ दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ भी एक पायदान आगे बढ़े हैं। वे नंबर तीन पर आ गए हैं। उनकी रेटिंग फिलहाल 833 की चल रही है। इस बीच लंबे समय से पहले नंबर पर कब्जा जमाए रहे ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड को नुकसान उठाना पड़ा है। वे अब तीन स्थानों के नुकसान के साथ सीधे नंबर 4 पर आकर गिरे हैं। उनकी रेटिंग 819 की रह गई है। साउथ अफ्रीका के टेस्ट कप्तान टेम्बा बावुमा 775 की रेटिंग के साथ नंबर 5 पर हैं। इस बीच भारतीय टीम के बल्लेबाजों की रैंकिंग पर कोई भी असर नहीं हुआ है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल 743 की रेटिंग के साथ नंबर 7 पर बने हुए हैं। वहीं यशस्वी जायसवाल 733 की रेटिंग के साथ नंबर 9 पर हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम भी 716 की रेटिंग के साथ नंबर 10 पर हैं।

शुभमन गिल ने मानव सुथार की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा- वह लंबे समय तक देश की तरफ से खेलेंगे

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में दस विकेट लेकर टीम की 165 रन से जीत में अहम भूमिका निभाने वाले बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार की जमकर प्रशंसा करते हुए कहा कि वह लंबे समय तक देश की तरफ से खेलेंगे। सुथार ने दूसरी पारी में 55 रन देकर छह और मैच में कुल 126 रन देकर 10 विकेट लिए। उन्होंने लगातार दूसरे मैच में पारी में पांच या इससे अधिक विकेट लेने का कारनामा किया। गिल ने मैच के बाद कहा, "वह शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। वह बहुत ही होनहार खिलाड़ी हैं। वह ऐसा खिलाड़ी है जो लंबे समय तक भारत के लिए खेल सकता है।" उन्होंने देवदत्त पडिक्कल की भी जमकर तारीफ की, जिन्हें पहली पारी में 167 और दूसरी पारी में 44 रन बनाने के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' का पुरस्कार मिला। साईं सुदर्शन के पैर के अंगूठे की चोट से नहीं उबरने के कारण पडिक्कल को तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने का मौका दिया गया था। गिल ने कहा, "उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखना शानदार था। शतक बनाना महत्वपूर्ण होता है, लेकिन शतक बनाने के बाद भी उन्होंने एक बड़ी पारी खेली। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की और दूसरी पारी में दबदबा बनाया, वह देखना अद्भुत था।" भारतीय कप्तान इस जीत से खुश थे क्योंकि इससे कुछ हद तक दबाव कम हुआ, हालांकि भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 53.33 प्रतिशत अंकों के साथ पांचवें स्थान पर बना हुआ है। उन्होंने कहा, "वह (डब्ल्यूटीसी फाइनल) हमारा अंतिम लक्ष्य है। टेस्ट में जीत आसानी से नहीं मिलती और यह जीत बेहद खुशी देने वाली है।" भारत के मैच जीतने के तुरंत बाद तेज बारिश शुरू हो गई और टीम को राहत मिली कि मौसम के देवता ने उनका खेल नहीं बिगाड़ा। गिल ने कहा, "यह हमारे लिए बेहद संतोषजनक जीत है। हम अच्छी स्थिति में थे, लेकिन मौसम के कारण हमें यकीन नहीं था कि मैच जारी रहेगा या नहीं, लेकिन टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया।" भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले पडिक्कल का मानना था कि श्रीलंका के बाएं हाथ के स्पिनरों का सामना करना कोई समस्या नहीं थी क्योंकि पिच पर ज्यादा उछाल नहीं थी। उन्होंने कहा, "यह थोड़ी धीमी पिच थी, ज्यादा उछाल नहीं मिल रही थी, इसलिए बाएं हाथ के बल्लेबाजों ने बाएं हाथ के स्पिनरों का सामना आसानी से कर लिया।

सिर्फ बालों पर हर महीने 29 हजार खर्च करती है महिला

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपना समय बचाने के लिए तरह-तरह के तरीके अपनाते हैं. सुपर रिच लोगों की जिंदगी में तो समय की कीमत अक्सर पैसे से भी ज्यादा मानी जाती है. यही बात अमेरिका की एक अटॉर्नी की कहानी से समझी जा सकती है. वह हर महीने अपने बाल सेट करवाने यानी सैलून ब्लोआउट पर करीब 300 डॉलर यानी 29 हजार रुपये से ज्यादा खर्च करती हैं. ⊙

जिस गधे से रोज ढोते हैं सामान, उसी ने खींची रेसिंग कार्ट

कराची में हुई गधों की रेस

पाकिस्तान में अजीबो-गरीब खेल होते रहते हैं, जैसे मुर्गों की लड़ाई, ऊंटों की रेस, कबूतरबाज़ी और पतंगबाज़ी जैसे कई और परंपरागत खेल आज भी यहां चलन में हैं. हम आपको बता रहे हैं गधा रेस के बारे में, जो कराची में आयोजित हुई.

दुनिया में एक ऐसी भी जगह है, जहां गधों की रेस होती है. ज्यादातर लोगों का पहला अंदाजा पाकिस्तान ही होगा, क्योंकि यहां मुर्गों की लड़ाई से लेकर ऐसी कई अजीबोगरीब परंपराएं आज भी चलन में हैं. इस बार बात हो रही है पाकिस्तान की "गधा रेस" यानी डोंकी कार्ट रेस की. इसका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है. यह रेस 16 अगस्त को कराची में हुई थी. वीडियो में गधे दो पहियों वाली गाड़ियां खींचते हुए सड़कों पर दौड़ते दिखे. रेस जीतने के बाद एक शख्स ने खुशी से अपने गधे को दोनों बाहों में भर लिया. गधे ने भी अपने बड़े-बड़े दांत दिखाए, देखने में लगा जैसे वो मुस्कुरा रहा हो. आसपास खड़े लोग यह देखकर हंस पड़े. यह सिर्फ मनोरंजन के लिए होने वाली रेस नहीं है. यह कराची की पुरानी लोक-संस्कृति का हिस्सा है, खासकर शहर के लयारी (Lyari) इलाके का. ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स पाकिस्तान एसोसिएशन के मुताबिक, लयारी के लोगों ने ही इस खेल को दशकों तक जिंदा रखा है. इसकी शुरुआत को लेकर एक दावा यह भी है कि यह परंपरा 18वीं सदी के औपनिवेशिक दौर तक जाती है, जब कराची के आसपास मछुआरे अपनी गाड़ियों से रेस लगाते थे. ⊙

गधों के नाम भी होते हैं दिलचस्प

लयारी में यह खेल हमेशा से लोकप्रिय रहा है. पहले बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, बच्चे, पूरे के पूरे परिवार रेस देखने आते थे. कई लोग अपने पसंदीदा गधे पर दांव भी लगाते थे. 2014 में सिंध फेस्टिवल के दौरान कराची में 50 गधों की रेस हुई थी, जिसमें गधों के नाम भी अजीब रखे गए थे. ⊙

5 महीने से था बेरोजगार

AI की मदद से मिली 1.5 करोड़ की जॉब

आज के समय में नौकरी पाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है. अच्छी डिग्री और सालों का अनुभव होने के बावजूद कई लोगों को लगातार इंटरव्यू देने पड़ते हैं और अच्छी नौकरी नहीं मिलती. ऐसे ही एक शख्स की कहानी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है.

इस शख्स ने बताया कि नौकरी जाने के बाद उसने करीब पांच महीने तक नई नौकरी खोजी, लेकिन बार-बार निराशा ही हाथ लगी. आखिर में उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली और उसकी यही रणनीति काम कर गई. अब उसे करीब ₹1.5 करोड़ सालाना पैकेज वाली नई नौकरी

मिल गई है. इस शख्स ने अपनी कहानी रेडिट पर शेयर की. उसने बताया कि वह लगभग 10 साल तक एक ही कंपनी में काम करता रहा था. इस दौरान उसे तीन बार प्रमोशन भी मिला. लेकिन फरवरी के आखिर में अचानक कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया. यह फैसला उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था. ⊙

जन्म लेते ही बच्चों पर हो जाता है मालिक का हक

गुलामों के द्वीप की अनूठी कहानी

दुनिया 21वीं सदी में पहुंच चुकी है. गुलामी को खत्म हुए भी कई देशों में 100 साल से ज्यादा हो चुके हैं. लेकिन इंडोनेशिया में एक ऐसा द्वीप है, जहां आज भी कुछ लोग जन्म लेते ही किसी और की संपत्ति माने जाते हैं. उन्हें बचपन से ही मालिक की सेवा करनी पड़ती है. बिना मजदूरी के खेतों में काम करना, घर के सारे काम संभालना और मालिक के हर आदेश का पालन करना उनकी जिंदगी का हिस्सा होता है. इतना ही नहीं, कई लोगों का आरोप है कि यहां गुलाम महिलाओं के साथ यौन शोषण और मारपीट जैसी घटनाएं भी होती हैं.यह कहानी इंडोनेशिया के सुम्बा द्वीप की है, जो बाली के मशहूर समुद्री तटों से महज दो घंटे की दूरी पर है. बाहर से देखने पर

यह जगह खूबसूरत झरनों, पहाड़ियों और समुद्र के बीच बसा एक शांत पर्यटन स्थल नजर आता है, लेकिन इसके भीतर सदियों पुरानी एक ऐसी परंपरा आज भी सांस ले रही है, जिसे दुनिया गुलामी कहती है.

'मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे आजाद हों'

सुम्बा के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति, जो खुद इसी व्यवस्था में पैदा हुआ, अपनी पहचान छिपाते हुए बताता है कि बचपन से ही उसे मालिक के खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया जाता था. वह कहता है, अगर मैं ठीक से काम नहीं करता था तो मुझे पीटा जाता था. मुझ पर पानी फेंका जाता था. स्कूल से लौटते ही खेतों में काम करना पड़ता था. ⊙

सनी देओल की 'बंटवारा 1947' पिछड़ी

तीन दिन में 100 करोड़ पार आवारापन-2

शुक्रवार 14 अगस्त के दिन बॉलीवुड पर दो दमदार फिल्मों की भिड़ंत हुई- बंटवारा 1947 और आवारापन 2. दोनों ही फिल्में अलग-अलग जॉनर से हैं, और अलग ऑडियंस के साथ आती हैं. रिलीज से पहले इस बॉक्स ऑफिस क्लैश को 50-50 समझा जा रहा था. मगर अब ये एक तरफा में बदल चुकी है, क्योंकि इमरान लगातार सनी की फिल्म को पछाड़ रहे हैं. इमरान हाशमी की आवारापन 2, सनी देओल स्टारर बंटवारा 1947 को पहले वीकेंड काफी पीछे छोड़ चुकी है. ओपनिंग डे पर ही 22 करोड़ के नेट कलेक्शन से इमरान की फिल्म ने मजबूत लीड ले ली थी. वहीं सनी की फिल्म सिंगल डिजिट में सिमट गई थी. शनिवार को दोनों ही फिल्मों ने तगड़ा जंप देखा. बंटवारा 1947 ने तो 150% से ज्यादा अपनी कमाई में इजाफा देखा था. आवारापन 2 भी अच्छी खासी कमाई करके दो दिनों में 50 करोड़ से ज्यादा का नेट कलेक्शन करके हिट साबित हो गई थी. मगर संडे का दिन सनी देओल की फिल्म के लिए उतना खास नहीं रहा, जैसा पिछला दिन हुआ था. तीसरे दिन कमाई 46.3% तक गिर गई. ⊙

मायावती का 2007 वाला दांव क्या ब्राह्मणों के सहारे BSP फिर बना पाएगी सत्ता की राह?

2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को चुनाव, लीगल और मीडिया से जुड़ी अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं।इसे पार्टी के पुराने 'सोशल इंजीनियरिंग' फॉर्मूले को फिर से मजबूत करने और ब्राह्मण वोटरों को बसपा के साथ जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।

बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले संगठन में बड़ा फैसला लेते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र को अहम जिम्मेदारी सौंपी है। ब्राह्मण समाज के प्रमुख चेहरे माने जाने वाले सतीश चंद्र मिश्र को चुनाव के साथ-साथ लीगल और मीडिया से जुड़ी जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। मायावती के इस कदम को ब्राह्मण वोटरों को बसपा के साथ जोड़ने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है।बसपा के लिए यह रणनीति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी लंबे समय से उत्तर प्रदेश की सत्ता से बाहर है। मायावती आखिरी बार 2012 तक मुख्यमंत्री रहीं और इसके बाद पार्टी लगातार कमजोर होती गई। मौजूदा समय में लोकसभा में बसपा का एक भी सांसद नहीं है और विधानसभा में पार्टी का एकमात्र विधायक भी अब नहीं रहा। ऐसे में 2027 का विधानसभा चुनाव मायावती के लिए केवल सत्ता में वापसी की कोशिश नहीं, बल्कि बसपा के राजनीतिक आधार को बचाए रखने की भी बड़ी परीक्षा है।मायावती के राजनीतिक इतिहास में 2007 का चुनाव सबसे सफल उदाहरण माना जाता है। उस समय उन्होंने दलित वोट बैंक के साथ ब्राह्मणों को जोड़ने की रणनीति अपनाई थी। बसपा ने 86 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिनमें 41 उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। मायावती ने प्रदेश में ब्राह्मण भाईचारा समितियां बनाईं और कई ब्राह्मण सम्मेलनों को संबोधित किया। पार्टी ने उस दौर में 'ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी बढ़ता जाएगा' जैसे नारों के जरिए सामाजिक गठजोड़ को मजबूत करने की कोशिश की थी।इस सोशल इंजीनियरिंग का फायदा बसपा को मिला और 2007 में पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर सरकार बनाई। मायावती ने सात ब्राह्मण नेताओं को अपनी सरकार में मंत्री भी बनाया। यही वजह है कि 2027 के चुनाव से पहले सतीश चंद्र मिश्र को प्रमुख भूमिका देना पुराने सामाजिक समीकरण की वापसी का संकेत माना जा रहा है।हालांकि 2007 और 2026 के उत्तर प्रदेश में जमीन-आसमान का अंतर है। 2007 में मुलायम सिंह यादव की सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल था। बीजेपी और कांग्रेस भी आज की तरह मजबूत स्थिति में नहीं थीं। इसके उलट 2014 के बाद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपना राजनीतिक आधार काफी मजबूत किया है। ब्राह्मण सहित कई सवर्ण समुदायों का बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है।बसपा के सामने दूसरी बड़ी चुनौती उसका पारंपरिक दलित वोट बैंक है। पिछले वर्षों में दलित मतदाताओं के एक हिस्से का समर्थन भी पार्टी से दूर हुआ है। इसलिए केवल ब्राह्मणों को साधने से मायावती के लिए सत्ता की राह आसान नहीं होगी। उन्हें दलित आधार को फिर मजबूत करने के साथ-साथ पिछड़े, मुस्लिम और अन्य सामाजिक समूहों में भी अपना प्रभाव बढ़ाना होगा।मायावती के सामने असली चुनौती 2007 के फॉर्मूले को दोहराना नहीं, बल्कि उसे 2027 के बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के मुताबिक नया रूप देना है। अब देखना होगा कि सतीश चंद्र मिश्र की सक्रिय भूमिका और ब्राह्मणों को साधने की कोशिश बसपा को फिर से उत्तर प्रदेश की मुख्य राजनीतिक धारा में कितनी मजबूती से ला पाती है।

लखनऊ के मैनकाइंड अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग का शिकंजा,, जांच पूरी होने तक नए मरीजों की भर्ती

लखनऊ के गुडंबा स्थित मैनकाइंड अस्पताल में दो दिन पहले हुई महिला की मौत के मामले में स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड़ में दिख रहा है। विभाग ने जांच पूरी होने तक अस्पताल के संचालन पर रोक लगा दी है। इसके तहत नए मरीजों की भर्ती और इलाज संबंधी गतिविधियों पर भी रोक रहेगी। निजी अस्पतालों के नोडल अधिकारी डॉ. एपी सिंह की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम बुधवार को अस्पताल पहुंची। टीम ने अस्पताल में उपलब्ध दस्तावेज और महिला के इलाज से जुड़े रिकॉर्ड जांचे और संचालक के बयान लिए। अस्पताल के संचालन, पंजीकरण और उपचार से संबंधित जरूरी कागजात भी टीम ने जुटाए हैं। v डॉ.एपी सिंह ने बताया कि महिला की मौत किन परिस्थितियों में हुई। इसकी पड़ताल की जा रही है। टीम अस्पताल के दस्तावेजों और उपचार संबंधी रिकॉर्ड का मिलान करेगी। जांच में यह भी देखा जाएगा कि इलाज के दौरान किसी स्तर पर लापरवाही तो नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत के कारण और उपचार में लापरवाही की स्थिति स्पष्ट होगी। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर अस्पताल के खिलाफ आगे की कार्रवाई तय होगी।

यूपी के युवाओं को मिलेगा ग्लोबल रोजगार का रास्ता कौशल विकास मिशन में बना इंटरनेशनल एम्पलॉयमेंट सेल

प्रदेश के युवाओं को देश के साथ वैश्विक रोजगार बाजार से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नई पहल की है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन में इंटरनेशनल एम्पलॉयमेंट सेल का गठन किया गया है। यह प्रकोष्ठ विदेशों में रोजगार के अवसरों की जानकारी जुटाने, विदेशी कंपनियों की मांग के अनुरूप युवाओं को प्रशिक्षित कराने और प्रशिक्षित युवाओं को पारदर्शी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय रोजगार से जोड़ने का काम करेगा। व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुरूप बेहतर रोजगार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवा प्रतिभा और क्षमता में किसी से पीछे नहीं हैं। इंटरनेशनल एम्पलॉयमेंट सेल के माध्यम से प्रशिक्षित युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसरों से जोड़ने की प्रभावी व्यवस्था तैयार की जा रही है।मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य की दिशा में यह पहल महत्वपूर्ण है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत 35 प्रमुख सेक्टरों में 1,300 से अधिक जॉब रोल के लिए युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब इन प्रशिक्षित युवाओं को वैश्विक रोजगार बाजार से जोड़ने पर विशेष जोर दिया जाएगा। इंटरनेशनल एम्पलॉयमेंट सेल केंद्र सरकार के विदेश मंत्रालय में पंजीकृत रिक्रूटिंग एजेंटों, सेवायोजन निदेशालय, मिशन रोजगार और अन्य संबंधित संस्थाओं के साथ समन्वय करेगा। विदेशों में कंपनियों की मानव संसाधन संबंधी मांग के आधार पर प्रशिक्षित युवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। सेल में डॉ. एमके सिंह, सहायक निदेशक को अध्यक्ष और विजय नामदेव, सहायक प्रबंधक को नोडल अधिकारी बनाया गया है। सेल प्रत्येक 15 दिन में मिशन रोजगार सेल के साथ बैठक कर विभिन्न देशों और सेक्टरों में उपलब्ध रोजगार की नई मांग की जानकारी जुटाएगा। इसके आधार पर योग्य युवाओं का डेटाबेस तैयार कर संबंधित एजेंसियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

शिवलिंग पर लगे चांदी के आवरण को हटाकर सीधे जलाभिषेक की अनुमति देने की मांग

बुद्धेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक के लिए परियर (बिठूर) गंगाघाट से निकली नंगे पांव कांवड़ यात्रा बुधवार को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के जीरो प्वाइंट स्थित मोहान रोड पहुंची। यहां बैदेही सेना के नेतृत्व में करीब 3,500 कांवड़ियों ने शिवलिंग पर लगे चांदी के आवरण को हटाकर सीधे जलाभिषेक की अनुमति देने की मांग को लेकर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे मोहान रोड पर भीषण जाम लग गया। कई एंबुलेंस और जरूरी वाहनों के फंसने से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कांवड़ियों का कहना है कि वे परियर गंगाघाट से गंगाजल लेकर नंगे पांव पैदल बुद्धेश्वर महादेव मंदिर जा रहे हैं। उनकी मांग है कि जलाभिषेक के समय शिवलिंग पर लगा चांदी का आवरण हटा दिया जाए, जिससे श्रद्धालु प्रत्यक्ष दर्शन करते हुए सीधे शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ा सकें। उन्होंने प्रशासन और मंदिर प्रबंधन से समय रहते इस संबंध में निर्णय लेने की मांग की। बैदेही सेना के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राजू, महंत अनमोल द्विवेदी और महामंत्री अभिषेक मिश्रा ने बताया कि यात्रा का उद्देश्य श्रद्धालुओं की आस्था के अनुरूप शांतिपूर्ण तरीके से बुद्धेश्वर महादेव का जलाभिषेक करना है। सूचना पर एसीपी काकोरी शकील अहमद के साथ पारा और काकोरी पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने कांवड़ियों को समझाकर सड़क से हटाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़े रहे। सड़क जाम होने से मोहान रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। एंबुलेंस समेत अन्य जरूरी वाहनों के फंसने के कारण स्थिति और गंभीर हो गई। पुलिस यातायात व्यवस्था सामान्य कराने के साथ ही कांवड़ियों से बातचीत कर समाधान निकालने में जुटी रही।

लखनऊ में चार दिन से बारिश का दौर जारी, 117.7 मिमी बरसा पानी

राजधानी लखनऊ में पिछले चार दिनों से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। बुधवार को शहर के कुछ इलाकों में रिमझिम बारिश हुई, जबकि सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक बारिश और गरज-चमक का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। मंगलवार को 24 घंटे में लखनऊ में 42.2 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। इससे पहले 15 से 17 अगस्त के बीच 75.5 मिमी बारिश हुई थी। इस तरह चार दिनों में राजधानी में कुल 117.7 मिमी पानी बरसा। लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। मंगलवार को जानकीपुरम, संजय गांधी पुरम, अलीगंज और फैजुल्लागंज समेत कई क्षेत्रों में जबरदस्त जलभराव हुआ। कई जगह लोगों को घरों से बाहर निकलने में परेशानी हुई, जबकि कुछ घरों में भी पानी पहुंच गया। लगातार बारिश के कारण सोमवार को निगोहां और बुधवार को मदेयगंज व गोसाईंगंज में घरों की दीवारें गिरने की घटनाएं भी हुईं। हालांकि, इनमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

अखिलेश यादव ने आजम खान से जुड़े 10 ठिकानों पर ED की छापेमारी को लेकर भाजपा सरकार को जमकर घेरा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के ठिकानों पर आज यानी बुधवार सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी को लेकर भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह पूरी कार्रवाई केवल 1-2 फीसदी सांप्रदायिक सोच रखने वाले समर्थकों को संतुष्ट करने के लिए की जा रही है।यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि शिक्षा और शिक्षार्थियों के विरोधी तथा स्कूल बंद करवाने वाले भाजपाई आज यूनिवर्सिटी बनाने वाले शख्स के खिलाफ ED की छापेमारी करवा रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि उन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जो आपराधिक कांडों में संलिप्त हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ऐसा सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि वह अपने बचे हुए 1 से 2 प्रतिशत संकीर्ण और सांप्रदायिक सोच वाले कुतर्की समर्थकों को किसी तरह खुश कर सके। अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कई अन्य बड़े घोटालों का भी जिक्र किया। उन्होंने सवाल उठाया कि सत्ता से जुड़े असली भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं

हो रही है? सपा प्रमुख ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, रेलवे की बदहाली, स्कूलों और सड़कों की खस्ताहाल स्थिति जैसे मुद्दों को उठाया। इसके साथ ही उन्होंने भ्रष्ट पुलिसकर्मियों, महाकुंभ के कामों में भ्रष्टाचार और स्मार्ट सिटी के नाम पर हो रहे खरबों रुपये के खेल को लेकर भी राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा।आपको बता दें कि बुधवार सुबह ED की अलग-अलग टीमों ने वरिष्ठ सपा नेता आजम खान और उनके करीबियों के रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली समेत 10 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। यह बड़ी कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ED की टीमें मुख्य रूप से आजम खान के वित्तीय लेनदेन और संदिग्ध फंडिंग की गहराई से जांच कर रही हैं। इसी कड़ी में मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के परिसरों में मौजूद डिजिटल साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है। इस छापेमारी का मकसद अपराध से अर्जित आय, वित्तीय रिकॉर्ड और सरकारी धन के दुरुपयोग से जुड़े अहम दस्तावेज व डिजिटल सबूत जुटाना है।

उन्नाव के कस्तूरबा विद्यालय का औचक निरीक्षण दो शिक्षिकाएं और दोनों रसोइयां मिलीं अनुपस्थित

उन्नाव के हिलौली विकासखंड स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय मौरावां का बुधवार दोपहर एसडीएम पुरवा ब्रजेश शुक्ला ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दो पूर्णकालिक शिक्षिकाएं अनुपस्थित मिलीं, जबकि विद्यालय में तैनात दोनों रसोइयां पिछले पांच दिनों से ड्यूटी पर नहीं आई थीं। उनकी अनुपस्थिति में प्रभारी वार्डन छात्राओं के लिए भोजन तैयार करती मिलीं। एसडीएम ने विद्यालय में छात्राओं की उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था, भोजन, सुरक्षा और मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। विद्यालय में कुल पांच पूर्णकालिक शिक्षिकाएं तैनात हैं। इनमें ज्योति चौधरी और योगिता अनुपस्थित मिलीं। दोनों की ओर से ऑनलाइन अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र दिए जाने की जानकारी दी गई। इसके अलावा प्रीति यादव और सविता देवी अंशकालिक शिक्षिकाओं के रूप में कार्यरत हैं। कक्षा छह से आठ तक विद्यालय में 100 छात्राएं नामांकित हैं, जिनमें से निरीक्षण के दौरान 87 उपस्थित मिलीं। वहीं, कक्षा नौ और दस में 51 छात्राओं का नामांकन है, जिनमें 19 छात्राएं उपस्थित थीं। बताया गया कि कक्षा नौ और दस की छात्राएं करीब दो किलोमीटर दूर स्थित केएनपीएन विद्यालय मौरावां में पढ़ने जाती हैं। इनकी उपस्थिति ऑफलाइन के साथ प्रेरणा पोर्टल पर भी दर्ज की जाती है। निरीक्षण के दौरान पता चला कि विद्यालय की दोनों रसोइयां पिछले पांच दिनों से ड्यूटी पर नहीं आ रही हैं। ऐसे में प्रभारी वार्डन सुरभि सिंह स्वयं छात्राओं के लिए भोजन तैयार कर रही हैं। निरीक्षण के समय मीनू के अनुसार दूध-दलिया, कढ़ी-चावल, मौसमी सब्जी, सलाद और रोटी तैयार मिली। रसोई में रखे दाल, चावल और अन्य खाद्यान्न की गुणवत्ता भी संतोषजनक पाई गई। एसडीएम ने विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था भी देखी। कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे चालू मिले, लेकिन आवासीय परिसर के गेट पर कैमरा नहीं लगा था। इसे सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल लगाए जाने की आवश्यकता बताई गई। हॉस्टल में एक चौकीदार भी तैनात मिला। विद्यालय नगर पंचायत मौरावां के अंतर्गत आने के कारण यहां कायाकल्प योजना का काम नहीं हुआ है। हालांकि, फर्श बना हुआ मिला और वाटर कूलर चालू स्थिति में था। बिजली व्यवस्था के लिए जनरेटर और इनवर्टर उपलब्ध हैं। विद्यालय में जियो फाइबर वाई-फाई की सुविधा भी है, लेकिन कंप्यूटर लैब अभी तक तैयार नहीं हुई है। वहीं, एक डॉर्मिटरी और एक लैब का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन बताया गया।

बरसात में पानी निकासी न हो पाने से दो हजार बीघा फसल जलमग्न

गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के दौरान डंपरों के निकलने के लिए निहालपुर-भदनी नाले को बंद कर रास्ता बनाया गया था। काम पूरा होने के बाद भी इसे खोला नहीं गया। बरसात में पानी निकासी न हो पाने से दो हजार बीघा फसल जलमग्न हो गई। इससे परेशान किसानों ने एसडीएम से समस्या के निराकरण की मांग की है। क्षेत्र के बृजपालपुर, भैंसंहरा, मवई लाल, मवईभान आदि गांवों के किसान मंगलवार को तहसील पहुंचे। उन्होंने एसडीएम फाल्गुनी सिंह को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार अशोक कुमार शुक्ला को सौंपा। ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र का पानी निहालपुर से होकर भदनी झाल तक नाले से जाता है। एक साल पहले गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए मिट्टी ले जाने वाले डंपरों के लिए निहालपुर के पास नाले में मिट्टी भरकर रास्ता बनाया गया था। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद इस नाले को खोला नहीं गया। बरसात में पानी निकासी अवरुद्ध होने से लगभग दो हजार बीघा धान की फसल जलमग्न हो गई है। खेतों में पानी ऐसे ही भरा रहा तो फसल सड़ जाएगी। किसानों ने एसडीएम से मामले को गंभीरता से लेते समस्या के समाधान की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में शिवलखन सिंह, राजेश यादव, जगतपाल, रमेश यादव, रघुवीर प्रसाद, रामदीन, सतीश, प्रेम, साहबलाल, द्वारिका प्रसाद, सतीश गौड़, शिवराज, रामलखन, हरेंद्र कुमार, शिवकांत यादव, सुनील यादव, मान सिंह किसान रहे। एसडीएम फाल्गुनी सिंह ने बताया कि शिकायत मिली है। जांच करा कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

उन्नाव में सर्वोदय विद्यालय के सैकड़ों छात्रों का प्रदर्शन खराब भोजन-पानी और शिक्षकों की कमी पर मोहान चौराहा जाम

उन्नाव जिले के हसनगंज क्षेत्र की न्योतनी नगर पंचायत में संचालित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय के सैकड़ों छात्रों ने बुधवार सुबह अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। छात्र हाथों में तख्तियां लेकर मोहान चौराहे पर पहुंचे और सड़क पर धरने पर बैठकर यातायात बाधित कर दिया। छात्रों के प्रदर्शन के चलते चौराहे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा।छात्रों का आरोप है कि विद्यालय में लंबे समय से भोजन की गुणवत्ता ठीक नहीं है। उन्हें मानक के अनुरूप और गुणवत्तापूर्ण खाना नहीं मिल रहा है। इसके अलावा पेयजल व्यवस्था भी संतोषजनक नहीं होने की शिकायत छात्रों ने की है। छात्रों का कहना है कि स्कूल में पढ़ाई के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक भी उपलब्ध नहीं हैं, जिससे उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है।प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने विद्यालय की प्रधानाचार्य वंदना के व्यवहार को लेकर भी नाराजगी जताई। छात्रों का आरोप है कि अपनी समस्याओं को कई बार प्रधानाचार्य के सामने रखा गया, लेकिन उनकी शिकायतों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। छात्रों ने कहा कि भोजन, पेयजल और शिक्षकों की कमी की समस्या काफी समय से बनी हुई है।बुधवार सुबह करीब छह बजे बड़ी संख्या में छात्र मोहान चौराहे पर पहुंच गए। प्रदर्शन और सड़क जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। कोतवाल शरद कुमार, सीओ तेज बहादुर सिंह, अजगैन, सोहरामऊ और पुरवा क्षेत्र के पुलिस अधिकारी तथा सीओ अरविंद चौरसिया समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। एडीएम और एसडीएम के साथ समाज कल्याण विभाग के अधिकारी भी छात्रों से बातचीत करने पहुंचे।अधिकारियों ने छात्रों को समझाने और उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन देकर जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहे। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, वे धरना समाप्त नहीं करेंगे।छात्रों ने समाज कल्याण विभाग के मंत्री को मौके पर बुलाने की मांग भी रखी है। फिलहाल प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के अधिकारी छात्रों से बातचीत कर स्थिति को शांत करने और यातायात व्यवस्था बहाल कराने की कोशिश में जुटे हैं। छात्रों की शिकायतों की जांच और विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है, इस पर सभी की नजर है।

उन्नाव में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने उठाई 11 सूत्रीय मांगें, डीआईओएस को सौंपा ज्ञापन

उन्नाव में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षणेत्तर संघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित 11 सूत्रीय ज्ञापन जिला विद्यालय निरीक्षक को सौंपा। संगठन के जिलाध्यक्ष कालीशंकर बाजपेई के नेतृत्व में पदाधिकारी शाम करीब चार बजे जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पहुंचे और लंबित मांगों के जल्द निस्तारण की मांग की।संघ ने शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को शिक्षक पद पर पदोन्नति देने की मांग प्रमुखता से उठाई। इसके अलावा राज्य कर्मचारियों की तर्ज पर 300 दिनों के उपार्जित अवकाश का नकदीकरण करने और कर्मचारियों को निशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। संगठन ने विद्यालयों की प्रबंध समितियों में शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।ज्ञापन में हाईस्कूल और इंटरमीडिएट विद्यालयों में कार्यरत लिपिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने और 22बी का लाभ देने समेत अन्य मांगें शामिल हैं। पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षणेत्तर कर्मचारी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और विद्यालयों के प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने में उनकी अहम भूमिका रहती है।संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि लंबे समय से कई मांगें लंबित हैं, जिससे कर्मचारियों में असंतोष है। सरकार को इन समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द निर्णय लेना चाहिए। उनका कहना है कि मांगों के समाधान से कर्मचारियों के हितों की रक्षा होगी और विद्यालयों में प्रशासनिक कार्यों के बेहतर संचालन के साथ समन्वय भी मजबूत होगा। इस दौरान मंडलीय मंत्री दिवाकर सिंह, जिला मंत्री अमित चौरसिया, अनिल कुशवाहा, राम जीवन, सौरभ कुमार दीक्षित, अविनाश कुमार, भरत, अविनाश कुमार यादव और धर्मेंद्र यादव समेत संगठन के अन्य पदाधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे।

हड़हरा गांव में नागपंचमी पर दंगल का आयोजन किया गया

हिलौली क्षेत्र के हड़हरा गांव में सोमवार को नागपंचमी पर दंगल का आयोजन किया गया। इसमें क्षेत्रीय पहलवानों ने दमखम के साथ दांवपेंच दिखाए। फाइनल कुश्ती में पहलवान इंद्रराज ने जयकरन सिंह को पटकनी देकर दंगल केसरी का खिताब जीता। दंगल में 34 कुश्तियां हुईं। पहलवानों ने एक-दूसरे को पटकनी देने के लिए विभिन्न दांवपेंच आजमाए। अंतिम मुकाबला बैसनखेड़ा के जयकरन सिंह और इंद्रराज के बीच हुआ। दोनों पहलवानों के बीच काफी देर तक कड़ा मुकाबला चलता रहा। आखिर में इंद्रराज ने जयकरन सिंह को पटकनी देकर फाइनल मुकाबला नाम कर दंगल केसरी का खिताब हासिल किया। प्रतियोगिता में अमन पारा, प्रांजुल व अभिषेक राजाखेड़ा, रामसुमेर लउवा, गौरव सिंह, मिथिलेश व अचल लउवा, सचिन, बिपिन, विवेक, सुमित, रोशन, अरुण, रमन, विपिन और विकास ने कुश्ती के जौहर दिखाए। दंगल रेफरी रामकुमार यादव रहे। इस मौके पर मनोज भारती, सुरेश साहू, बच्चू यादव, बरखंडी यादव, हृदयनारायण यादव, कल्लू मिश्रा, बउवा साहू, हिमांशू सिंह, सचिन यादव, जानू साहू, रामसिंह यादव और अखिलेश आदि मौजूद रहे।

उन्नाव जिला अस्पताल में पिछले तीन दिनों से एक्स-रे मशीन खराब

उन्नाव जिला अस्पताल में पिछले तीन दिनों से एक्स-रे मशीन खराब है। इसके चलते मरीजों को जांच कराने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को भी डॉक्टर द्वारा एक्स-रे की सलाह दिए जाने के बाद मरीज और उनके तीमारदार जांच के लिए अस्पताल परिसर में भटकते रहे। मशीन खराब होने के कारण कई मरीजों को मजबूरी में निजी जांच केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है। अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों की संख्या अधिक होती है। हड्डी में चोट, दुर्घटना, सीने और अन्य बीमारियों से संबंधित मामलों में डॉक्टर अक्सर एक्स-रे कराने की सलाह देते हैं। लेकिन पिछले तीन दिनों से मशीन खराब होने के कारण अस्पताल में यह महत्वपूर्ण सुविधा बाधित है। मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पताल में इलाज कराने का मुख्य उद्देश्य कम खर्च में बेहतर चिकित्सा सुविधा प्राप्त करना होता है। एक्स-रे मशीन खराब होने के बाद उन्हें निजी केंद्रों पर जांच कराने के लिए जाना पड़ रहा है, जिससे जांच शुल्क के साथ आने-जाने का अतिरिक्त खर्च भी उठाना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए यह खर्च काफी मुश्किल पैदा कर रहा है।

UP-Japan Investment Meet 2026: सीएम योगी ने जापानी निवेशकों को दिया यूपी में निवेश का न्योता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश और जापान के रिश्तों को आर्थिक साझेदारी के साथ-साथ साझा सभ्यतागत और सांस्कृतिक विरासत से भी जोड़ा।उन्होंने यूपी को भारत का 'फूड बास्केट' और 'अनलिमिटेड पोटेंशियल' वाला राज्य बताते हुए कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी और खाद्य प्रसंस्करण में निवेश की संभावनाएं गिनाईं।

UP-Japan Investment Meet 2026 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का उल्लेख करते हुए जापान के साथ मजबूत संबंधों की बात कही। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और जापान के रिश्ते केवल आर्थिक साझेदारी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि दोनों के बीच प्राचीन सभ्यतागत विरासत का भी गहरा संबंध है। सीएय योगी ने कहा कि जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है तो यूपी लैंड ऑफ सूर्यवंश है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश को भारत का 'फूड बास्केट' बताया और कहा कि देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 21 प्रतिशत है। उन्होंने राज्य में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर भी जोर दिया।सीएम योगी ने जापान और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान का उल्लेख करते हुए कहा कि जापान को 'लैंड ऑफ राइजिंग सन' कहा जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश 'लैंड ऑफ सूर्यवंश' और 'लैंड ऑफ श्रीराम' है। उन्होंने यूपी को 'लैंड ऑफ श्रीकृष्ण', 'लैंड ऑफ बुद्ध' और 'लैंड ऑफ अनलिमिटेड पोटेंशियल' भी बताया।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर जैसे महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थस्थल हैं, जो राज्य की पहचान को दुनिया के स्तर पर मजबूत बनाते हैं। उन्होंने भगवान बुद्ध से जुड़े काला नमक चावल का भी उल्लेख किया और बताया कि यह उत्तर प्रदेश की वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का हिस्सा है।सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन और स्पष्ट नीयत के साथ उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप थ्री इकोनामी में शामिल होते हुए भारत का ग्रोथ इंजन बना है। बीते 9 वर्षों में हमने सुरक्षा, स्थायीत्व के साथ उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को तीन गुना करने में सफलता प्राप्त की है।1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की दिशा में हम तेजी से आगे बढ़े हैं।सीएम योगी ने कहा कि आज 96 लाख से अधिक MSMEs, 35,000 से अधिक बड़े उद्योग और 22 हजार से अधिक Startups उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं। 75 हजार एकड़ से ज्यादा डेडिकेड इंडस्ट्रियल लैंड बैंक उपलब्ध है। सीएम योगी ने कहा कि यूपी निवेश और नवाचार के नए केंद्र के रूप में उभरा है। देश के मोबाइल उत्पादन का 55 फीसदी मैनुफैक्चरिंग यूपी में हो रहा हैसीएम योगी ने कहा कि भारत-जापान के Strategic Vision को अब उत्तर प्रदेश और जापानी उद्योग के बीच इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग एवं टेक्नोलॉजी पार्टरनरशिप के माध्यम से एक Concrete Economic and Industrial Partnership में परिवर्तित करने का यह सबसे बेहतर समय है। सीएम योगी ने कहा कि आज 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की एस्कॉर्ट कुबोटा परियोजना के तहत लगभग 4,000 रोजगार सृजन की जो संभावना विकसित हुई है, इसके प्रथम चरण में प्रतिवर्ष 60,000 ट्रैक्टर और 15,000 Construction Equipment के उत्पादन की क्षमता प्रस्तावित की गई है.सीएम योगी ने कहा कि जापानी उद्योग की सबसे बड़ी ताकत है क्वालिटी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की सोच, हमरा उद्देश्य यूपी में लॉन्ग टचर्म एंड स्टारंग जापानी इंडस्टिरयल इकोसिस्टम विकसित करना, और जापान को एक प्रमुख साझेदार के रूप में स्थापित करना। यूपी सरकार एक विश्वसनीय सहयोगी के तौर पर खड़ी है। उल्लेखनीय है कि इस साल फरवरी महीने में सीएम योगी ने जापान का दौरा किया था। उन्होंने वहां के उद्योगपतियों और निवेशकों से मुलाकात की थी। भारत और जापान के संबंध को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा था कि सूर्य की प्रथम किरण से प्रारंभ होकर और सूर्यवंश की धरा उत्तर प्रदेश को एक आत्मीय संवाद के साथ जोड़ता है।

इमरान मसूद और सपा विधायक आशु मलिक के बीच तीखी नोकझोंक ?

सहारनपुर में ज़िला विकास समन्वय और निगरानी समिति (DISHA) की बैठक के दौरान कांग्रेस सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक के बीच हुई तीखी बहस की खबरों को दोनों नेताओं ने बुधवार को कम करके आंका। मसूद ने कहा कि कोई झगड़ा नहीं हुआ और मलिक ने इस घटना को कोई बड़ी बात नहीं बताया। खबरों के मुताबिक, इमरान मसूद की अध्यक्षता में हुई बैठक में नाली बनाने के मुद्दे पर बहस हुई। बैठक में ज़िले के वरिष्ठ अधिकारी, SP सांसद इकरा हसन और अन्य विधायक भी मौजूद थे। ANI से बात करते हुए मलिक ने कहा कि बैठक का मकसद जनहित के मुद्दों पर चर्चा करना था और वह अपने निर्वाचन क्षेत्र से जुड़े मामले उठा रहे थे। मलिक ने कहा कि कल सहारनपुर विकास भवन में DISHA की बैठक हो रही थी, जिसमें सभी अधिकारी मौजूद थे। यह कोई रैली नहीं थी जहाँ भाषण दिए जा रहे हों। हम अपनी बातें रख रहे थे, और 80 प्रतिशत मुद्दे हमारे ही थे। इसके लिए हमें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मलिक ने मसूद के साथ हुई बहस की बात को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और कहा कि राजनीतिक नेताओं के बीच ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। SP विधायक ने कहा कि हमारे बीच ऐसा कोई झगड़ा या बहस नहीं हुई। मीटिंग या रैलियों के दौरान दो नेताओं के बीच ऐसी बातें होती रहती हैं; यह कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाए बिना नहीं हटते। उन्होंने कहा कि वह मीटिंग को ठीक से चलाने के लिए नियमों का ज़िक्र कर रहे थे और उन्होंने कहा कि वह जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे।

बदायूं में सड़क पर टहलता दिखा मगरमच्छ

बदायूं के कछला कस्बे में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब वार्ड नंबर-1 की सड़क पर अचानक एक मगरमच्छ दिखाई दिया। सुबह-सुबह सड़क पर मगरमच्छ के पहुंचने की खबर आग की तरह फैल गई। देखते ही देखते आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। कई लोगों ने सुरक्षित दूरी से वीडियो बनाना शुरू कर दिया, जबकि कुछ ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलते ही वन विभाग और नगर पंचायत की टीम मौके पर पहुंची। वन दरोगा शुभम प्रताप सिंह के नेतृत्व में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। उनके साथ वन दरोगा आदित्य गंगवार और वनरक्षक विकेंद्र कुमार सहित टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे। टीम ने पहले आसपास मौजूद लोगों को पीछे हटाया, ताकि किसी तरह की अनहोनी न हो। इसके बाद पूरी सतर्कता और सावधानी के साथ मगरमच्छ को काबू करने का अभियान शुरू किया गया। करीब काफी देर की मशक्कत के बाद वन विभाग की टीम मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ने में सफल रही। रेस्क्यू पूरा होते ही लोगों ने राहत की सांस ली। इसके बाद मगरमच्छ को वाहन से ले जाकर ढकनगला गांव के पास उसके प्राकृतिक आवास के अनुकूल सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया गया। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल यह पता लगाया जा रहा है कि मगरमच्छ आबादी वाले इलाके और सड़क तक कैसे पहुंचा। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि गंगा नदी के किनारे जलस्तर में बदलाव या आसपास के जलभराव के कारण वह भटककर रिहायशी क्षेत्र तक आ गया होगा। हालांकि वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है।

श्यामलाल पाल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा

समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर पर भी कटाक्ष किया। श्यामलाल पाल ने कहा कि राजभर एक गैर-राजनीतिक व्यक्ति हैं और कैबिनेट मंत्री पद पर रहते हुए भी वह अपने समाज का आरक्षण नहीं बचा पा रहे हैं। श्यामलाल पाल मुजफ्फरनगर में आयोजित सपा के एक अहम कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे। सम्मेलन से पहले उन्होंने बुधवार सुबह पार्टी सांसद हरेंद्र मलिक के आवास पर मीडिया से विस्तार से बातचीत की।सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ किया कि पार्टी के सभी नेता और कार्यकर्ता 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुटे हुए हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि आगामी चुनाव में उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार को सत्ता से हटाकर सामाजिक न्याय की सरकार बनाई जाएगी। श्यामलाल पाल ने कहा कि 2027 चुनाव के लिए पार्टी की PDA रणनीति पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने बताया कि PDA का मतलब पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग है। इसके साथ ही उन्होंने इसमें समाज के सभी दुखी, पीड़ित और अपमानित लोगों को भी शामिल करते हुए कहा कि इन सभी वर्गों की समस्याओं को दूर करने का काम PDA ही करेगा।श्यामलाल पाल ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार को पूरी तरह से शिक्षा विरोधी करार दिया। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में 26 हजार से अधिक प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया है और माध्यमिक विद्यालयों की स्थिति भी बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने प्रदेश के विश्वविद्यालयों में हो रही कार्रवाई को लेकर भी योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में मौजूदा सरकार की नीतियां हमारे संविधान की मूल भावना के बिल्कुल विपरीत हैं।